

to absorb additional funds. It was decided by the committee consisting of officers from the State Government, my Ministry and the Cabinet Secretary.

The additional funds which have been given this year are over and above the normal allocation. For the year 1998-99, Rs. 37 crores have been provided in the Annual Plan of Orissa Government. Additional funds of Rs. 39 crores have been given.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, it is the most drought-prone area where continuously starvation deaths are taking place. Whenever such things happen, these are focussed in the media. Then political leaders visit that area and make a lot of statements. Afterwards, the successive Governments are forgetting the development of that area. My question is this: Will the Central Government, in consultation with the State Government, involve Members of Parliament and Members of the Legislative Assembly belonging to these three districts with regard to implementation of this long-term action plan to tackle the poverty alleviation programmes, including giving a major thrust to irrigation in that area.

SHRI BABAGOUDA PATIL: Yes, Sir, we are making that exercise.

श्री गांधी आजाद : सभापति महोदय, प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि उड़ीसा राज्य सरकार को 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए क्रमशः 164.03 करोड़ रुपया, 181.82 करोड़ रुपया और 193.28 करोड़ रुपया जारी किया गया है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि इस योजना में जो रुपया खर्च किया जा रहा है उसमें से एस.सी/एस.टी. के कल्याण के लिए कितना है ?

SHRI BABGOUDA PATIAL: Sir, the SC/ST component is there in every programme, but it varies from programme to programme.

ISI threat to Dwarka and Somnath temples

*346. SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether twelve shrines including Dwarka and Somnath temples are under threat of an attack from ISI backed subversive outfits;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government had issued any circular to the State Governments and Union Territories in this regard; and

(d) if so, the details of the action taken by the State Governments/Union Territories till date in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b) There is no specific information regarding threat to Dwarka and Somnath temples and other shrines from ISI backed subversive outfits.

(c) and (d) The concerned State Governments have been, from time to time, advised to review the security arrangements at important shrines. The Central Government assists the State Governments by sharing intelligence and providing Central Para Military Forces as per their requirement.

SHRI GOVINDRAM MIRI: Mr. Chairman, Sir, it is well known that ISI activities are increasing in many parts of India. I learnt from Press reports that ISI bent upon creating communal and social tensions in India, including demolishing certain important and historical shrines, like Somnath and Dwarka temples. Sir, as you are aware, the Somnath temple was renovated by Sardar Ballabhbhai Patel, and it might be the special target

*The question was actually asked on the floor of the House by Shri Govindram Miri.

of ISI. This is my apprehension. Will the hon. Minister enlighten me on this matter?

SHRI L. K. ADVANI: I have already stated that there is no such specific information that Somnath and Ayodhya are being targeted by the ISI. Even so, because of subversive activities and the kind of threats we come to know, a general alert has been given to all States. In this case, I may inform that as per the information received from the Gujarat Government, special arrangements have been made for the security of these two temples and the concerned DGPs and the Range DIGs have been instructed to take all precautionary measures to maintain strict vigil and badobast schemes for the security of these two temples.

श्री राजनाथ सिंह “सूर्य” : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ जैसा उन्होंने कहा कि विशिष्ट प्रकार की सूचना किसी स्थान के बारे में नहीं हैं। परन्तु सामान्यतः गतिविधियों के कारण एक जनरल अलर्ट की स्थिति है, आई एस आई की गतिविधियों के बारे में। इस सदन में भी कई बार चर्चा हो चुकी है और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि एक व्हाइट पेपर इस संदर्भ में, इस सदन में लाया जायेगा क्योंकि दिन-प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जिन दिनों की घटना की चर्चा है उन दिनों मैं सोमनाथ में ही था। उसके कारण मैं बड़ा पैनिक में था। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में जो व्हाइट पेपर आना था वह कब तक आने की संभावना है? इन गतिविधियों के बारे में ध्यान रखने के लिए एक विशेष प्रकार का सेल क्रिएट किया जाना था, क्या वह क्रिएट किया जा रहा है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : क्योंकि इस आशय के समाचार अखबारों में छपे हैं जिनके आधार पर यह सवाल पूछा गया है। इस कारण स्वाभाविक है, इन स्थानों पर चिंता का भाव था, कहीं पैनिक भी थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा और सदन को भी बताया कि हम पूरी निगरानी करते रहें हैं। इस विषय में जब गुजरात सरकार या अन्य सरकारों से पूछा, जहां-जहां पर इस प्रकार का खतरा था, खासकर कार्यवाही की है और क्या उपाय किए हैं, इसकी उन्होंने हमको जानकारी दी थी। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, जहां तक श्वेतपत्र

का सवाल है, सरकार को यह निश्चय है कि आईएसआई की गतिविधियों के बारे में हम श्वेतपत्र प्रकाशित करेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि वह तैयार हो रहा है और इस सत्र की समाप्ति से पहले तैयार हो जाएगा। लेकिन जो ड्राफ्ट बना उसमें कुछ परिवर्तन जरूरी समझा गया और इसलिए हमने ड्राफ्ट प्रकाशित नहीं किया है लेकिन शीघ्र अवश्य करेंगे।

SHRI O. RAJGOPAL: The Question relates to ISI organisation's demolition activities of temples but the answer given is that there is no specific information regarding such ISI plans. I would like to know whether there are ISI sponsored organisations which are active at this stage. Specifically, with regard to Kerala, there were reports in newspapers that two famous temples, Shabarimalai and Guruvayur, also are targeted for demolition, I would like to know whether it has been brought to the notice of the Government and if so, what steps have been taken.

SHRI L. K. ADVANI: A general caution has been given to all the States. About Guruvayur and Shabarimalai, I would have to find out and I would need a specific notice but, in general, all States have been alerted on these designs of the ISI or its sponsored organisations to see that such kind of disruptive activities are not undertaken.

मौलाना अबेदुल्लाह खान आजमी : सर, मैं आपके जरिए, यह कहना चाहता हूँ कि चाहे मंदिर ध्वस्त करने वाले हों और चाहे मस्जिद ध्वस्त करने वाले हों, दोनों की मज्जमत करनी चाहिए। दोनों ही काम बहुत निदायक हैं। जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि मंदिर ध्वस्त किए जाएं वह भी मजहबी नहीं हैं और जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं कि मस्जिद ध्वस्त की जाए उनका भी धर्म से, मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं यह सवाल करना चाहता हूँ कि गुजरात के बारे में आई.एस.आई. के सिलसिले में जो चिंताजनक बातें आई हैं, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में अब तक आई.एस.आई. के कितने लोग पकड़े जा चुके हैं, वे कहाँ कहाँ थे और वे क्या क्या रक रहे थे?

†مولانا عبید اللہ خاں اعظمی: سر۔ میں آپکے ذریعہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے مندر دھوست کرنے والے ہوں اور چاہے مسجد دھوست کرنے والے ہوں۔ دونوں کی مزمت کرنی چاہئے۔ دونوں ہی کام بہت ہی ننداںک ہیں۔ جو لوگ اس طرح کی بھاونا رکھتے ہیں کہ مسجد دھوست کی جائے انکا بھی دھرم سے میرے خیال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ گجرات کے بارے میں آئی۔ ایس۔ آئی کے سلسلے میں جو فکر مندی والی باتیں آئی ہیں۔ کیا منتری جی یہ بتانے کی کرپا کرینگے کہ گجرات میں اب تک آئی۔ ایس۔ آئی کے کتنے لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ وہ کہاں کہاں تھے۔

MR. CHAIRMAN: Question Hour is ewf.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

ग्रामीण आवास और गरीबी उन्मूलन योजनाएं

*344. श्री राज मोहिन्दर सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छह माह के दौरान ग्रामीण आवास तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी कतिपय योजनाएं तैयार करके सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई थी :

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कौन-कौन सी हैं तथा ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर कुल कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है, और,

(ग) या इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण आवास क्षेत्र में नई पहलें सरकार के विचाराधीन हैं। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. अव्यवहार्य कच्चा मकानों को अर्द्धपक्का/पक्का मकानों में बदलने के लिए इंदिरा आवास योजना (आई ए वार्ड) राशि में से 20% राशि आवंटित करने का प्रस्ताव।

2. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आंबटन मानदंड को बदलने का प्रस्ताव।

3. इंदिरा आवास योजना के ऋण-सह-सब्सिडी घटक को प्राप्त करने का प्रस्ताव।

4. ग्रामीण आवास और हैबिटेड विकास के लिए अभिनव चरण चालू करने का प्रस्ताव।

5. ग्रामीण इमारत केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता का प्रस्ताव।

6. ग्रामीण आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव।

7. ग्रामीण आवास और हैबिसेट विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव

8. आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को इक्विटी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई भी नई योजना नहीं बनाई गई हैं। तथापि स्वरोजगार कार्यक्रमों के पुनर्गठन और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के सुदृढीकरण का प्रस्ताव है। ग्रामीण गरीब का पारिवारिक आय में सुधार करने और साथ ही निचले स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुकूल डिजाइन के लचीलेपन के लिए एक निश्चित उद्देश्य के साथ ग्रामीण युवा स्व-रोजगार कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिद्धा), गंगा कल्याण योजना और ग्रामीण महिला और बाल विकास (डवाकरा) को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना को सरल और कारगर बनाने का भी प्रस्ताव है।

इन योजनाओं के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।